नमो-नमो दुर्गे सुख करनी। नमो-नमो दुर्गे दुःख हरणी।।

बुधवार, 12 अगस्त, 2026 ।

वर्ष 19 । अंक 118 । पृष्ठ 4 ।

आरएनआई नंबर : RAJHIN/2007/20298

व्हाट्स एप नंबर : 85291-15101

Email : berisgnr@gmail.com

website: www.sandhyadep.world

साँध्यदीप

We Fight For Human Rights

श्रीगंगानगर में भी दो चरणों में हो सकते हैं नगरीय निकाय चुनाव!

श्रीगंगानगर। प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। चुनाव कितने चरणों में करवाए जाएंगे, इसे लेकर अभी राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है, लेकिन सरकारी दफ्तरों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक दो चरणों में मतदान करवाए जाने की चर्चाएं चल रही हैं। माना जा रहा है कि अगस्त के तीसरे सप्ताह के बाद कभी भी राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है और इसके साथ ही संबंधित निकाय क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो सकती है।

श्रीगंगानगर जिले की बात करें तो यहां नगर परिषद श्रीगंगानगर के साथ जिले की विभिन्न नगर पालिकाएं चुनाव प्रक्रिया के दायरे में आएंगी। चर्चाओं के अनुसार जिले में मतदान को दो चरणों में विभाजित किया जा सकता है। संभावित व्यवस्था में पहले चरण में श्रीगंगानगर नगर परिषद और सूरतगढ़ नगरपालिका के लिए मतदान करवाए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद दूसरे चरण में जिले की अन्य नगर पालिकाओं में मतदान करवाया जा सकता है।

दूसरे चरण में इन निकायों पर नजर : दूसरे चरण के संभावित मतदान में लालगढ़, सादुलशहर, केसरीसिंहपुर, श्रीकरणपुर, गजसिंहपुर, पदमपुर, रायसिंहनगर, श्रीबिजयनगर, अनूपगढ़ और घड़साना जैसे नगरीय निकाय शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि इन निकायों को किस चरण में रखा जाएगा और किस तारीख को मतदान होगा, इसका अंतिम निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम जारी करने के बाद ही स्पष्ट होगा। इस संभावित व्यवस्था को लेकर स्थानीय प्रशासन भी चुनावी तैयारियों के लिहाज से सक्रिय नजर आ रहा है। चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद मतदान केंद्रों, कार्मिकों की तैनाती, मतदाता सूचियों, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य चुनावी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी।

आचार संहिता के बाद बढ़ेगी राजनीतिक सक्रियता : चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है। विभिन्न वार्डों में संभावित प्रत्याशी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और राजनीतिक दल भी वार्डवार समीकरणों को लेकर मंथन कर रहे हैं।

नगर निकाय चुनाव स्थानीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि इन चुनावों का सीधा असर शहरों के विकास, सड़क, सफाई, पेयजल, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर पड़ता है। ऐसे में संभावित चुनाव कार्यक्रम को लेकर स्थानीय स्तर पर भी लोगों की नजर राज्य निर्वाचन आयोग की घोषणा पर टिकी हुई है।

अनूपगढ़ निकाय में भी बदला स्वरूप : अनूपगढ़ को लेकर भी नगरीय निकाय की स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। पूर्व में अनूपगढ़ को जिला घोषित किए जाने के बाद यहां के नगरीय निकाय को नगर परिषद का दर्जा दिया गया था। बाद में अनूपगढ़ को फिर से नगरपालिका बनाए जाने की प्रक्रिया हुई। ऐसे में आगामी चुनाव में अनूपगढ़ निकाय का स्वरूप भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार : फिलहाल दो चरणों में चुनाव करवाने की चर्चा को आधिकारिक कार्यक्रम नहीं माना जा सकता। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना और चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि श्रीगंगानगर जिले के कौन-कौन से निकाय किस चरण में शामिल होंगे और मतदान की तारीखें क्या रहेंगी।

बीएसएफ परिसर में घुसे युवक से खुफिया एजेंसियां करेंगी पूछताछ

रायसिंहनगर (सुखदीपसिंह सूदन)। रायसिंहनगर स्थित सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) कैम्पस में दीवार फांदकर प्रवेश करने वाले युवक से अब खुफिया एजेंसियां पूछताछ करेंगी। युवक को मंगलवार को बीएसएफ ने पुलिस के सुपुर्द कर दिया था। इसके बाद रायसिंहनगर पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवक की पहचान सुभाष पुत्र गोविंद, निवासी करणपुर के रूप में हुई है।

मामला सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील होने के कारण पुलिस अब युवक के बीएसएफ परिसर में प्रवेश करने के उद्देश्य और उसकी गतिविधियों से जुड़े तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक हरीशंकर के अनुसार युवक को पूछताछ के लिए जिला मुख्यालय स्थित संयुक्त पूछताछ केन्द्र लाया जाएगा, जहां विभिन्न खुफिया एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगी।

दीवार फांदकर कैम्पस में पहुंचा था युवक : प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक ने बीएसएफ कैम्पस में प्रवेश करने के लिए दीवार फांदी थी। सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण परिसर में इस तरह प्रवेश किए जाने से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। बीएसएफ की ओर से युवक को पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले किया गया।

अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर युवक वहां क्यों पहुंचा था और उसने कैम्पस में प्रवेश करने का प्रयास किस उद्देश्य से किया।

मोबाइल में मिला पाकिस्तान नंबर से संपर्क

जांच के दौरान युवक के मोबाइल फोन से पाकिस्तान के एक नंबर पर बातचीत किए जाने की जानकारी सामने आने की बात कही जा रही है। हालांकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह बातचीत वर्ष 2025 में हुई थी।

खुफिया एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास करेंगी कि उस नंबर पर किस व्यक्ति से बातचीत हुई थी, बातचीत का स्वरूप क्या था और उसका बीएसएफ कैम्पस में प्रवेश करने की घटना से कोई संबंध है या नहीं। मोबाइल फोन में मौजूद अन्य कॉल डिटेल, संपर्क नंबर और डिजिटल गतिविधियों की भी जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

पुराना संपर्क भी जांच के दायरे में : जांच एजेंसियों के लिए यह पहलू भी महत्वपूर्ण होगा कि पाकिस्तान नंबर से वर्ष 2025 में हुई बातचीत और वर्तमान घटना के बीच कोई संबंध है या नहीं। यदि दोनों घटनाओं के बीच कोई कड़ी सामने आती है तो जांच का दायरा बढ़ सकता है। वहीं यदि पूछताछ में कोई अन्य कारण सामने आता है तो उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल युवक के संबंध में किसी प्रकार का अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है। बीएसएफ जैसे संवेदनशील सुरक्षा परिसर में अनधिकृत प्रवेश और मोबाइल में विदेशी नंबर से संपर्क की जानकारी सामने आने के कारण एजेंसियां मामले को गंभीरता से लेकर पूछताछ करेंगी।

पुलिस और खुफिया एजेंसियों की जांच पर नजर : युवक के खिलाफ रायसिंहनगर थाने में मामला दर्ज होने के बाद अब पुलिस के साथ-साथ खुफिया एजेंसियों की पूछताछ से कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है। जांच में युवक की पृष्ठभूमि, उसके संपर्कों, मोबाइल गतिविधियों और कैम्पस में प्रवेश के वास्तविक उद्देश्य को प्रमुखता से देखा जाएगा।

सबसे अहम सवाल यही है कि सुभाष ने बीएसएफ कैम्पस में प्रवेश करने का प्रयास क्यों किया? क्या वह किसी सामान्य उद्देश्य से वहां पहुंचा था या उसके पीछे कोई अन्य कारण था—इसका खुलासा जांच और पूछताछ के बाद ही हो सकेगा।

प्राइवेट स्कूलों में अव्यवस्था से शिक्षा प्रणाली पर सवाल!

सादुलशहर के बाल भारती स्कूल में नौ वर्षीय दिवांश की करंट लगने से हुई मौत ने केवल एक परिवार को गहरे दुख में नहीं डुबोया है, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था के सामने एक बेहद गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है—क्या हमारे स्कूल बच्चों की सुरक्षा के लिए वास्तव में तैयार हैं?

एक बच्चा स्कूल में पढ़ने, सीखने और सुरक्षित वातावरण में समय बिताने जाता है। अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजते समय यह विश्वास करते हैं कि वहां उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी गंभीरता से निभाई जाएगी। ऐसे में यदि स्कूल परिसर में लगे वाटर कूलर जैसी सामान्य सुविधा में विद्युत सुरक्षा से जुड़ी कमी सामने आती है और उसकी कीमत एक मासूम की जान से चुकानी पड़ती है, तो इसे केवल एक सामान्य दुर्घटना कहकर आगे बढ़ जाना उचित नहीं होगा।

दिवांश अब हमारे बीच नहीं है। इस घटना का सबसे दर्दनाक पहलू यही है कि जिस स्थान को बच्चे के लिए सुरक्षित माना गया था, वहीं उसकी जिंदगी समाप्त हो गई। यदि स्कूल प्रबंधन स्तर पर रखरखाव में लापरवाही हुई है तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। साथ ही यह भी पता लगाया जाना आवश्यक है कि स्कूल में विद्युत उपकरणों की नियमित जांच, अर्थिंग, वायरिंग और सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा था या नहीं। लेकिन सवाल केवल एक स्कूल तक सीमित नहीं है।

क्या शिक्षा विभाग ने जिले के अन्य स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक जांच शुरू की है? : यदि अभी तक ऐसा कोई अभियान शुरू नहीं हुआ है तो यह चिंता का विषय है। एक गंभीर घटना के बाद विभाग को इंतजार नहीं करना चाहिए कि कहीं दूसरी घटना घटे और फिर कार्रवाई की जाए। हादसे के बाद जांच करने से अधिक महत्वपूर्ण है हादसे को रोकने के लिए पहले से व्यवस्था करना। प्राइवेट स्कूलों में बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। इन संस्थानों से अभिभावक फीस लेते समय केवल शिक्षा की उम्मीद नहीं करते, वे अपने बच्चों की सुरक्षा का भरोसा भी खरीदते हैं। इसलिए स्कूल संचालकों की जिम्मेदारी केवल परीक्षा परिणाम, भवन और सुविधाओं तक सीमित नहीं हो सकती। बिजली व्यवस्था, पानी की सुविधा, अग्नि सुरक्षा, भवन की स्थिति, सीसीटीवी, आपातकालीन निकास, प्राथमिक उपचार और अन्य मूलभूत सुरक्षा व्यवस्थाओं की नियमित जांच भी उतनी ही जरूरी है। सरकारी स्कूल भी इस जांच से बाहर नहीं होने चाहिए। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हों या निजी स्कूल में, उनकी जिंदगी का मूल्य समान है। सुरक्षा के मानक भी समान होने चाहिए। शिक्षा विभाग को अब कागजी खानापूर्ति से आगे बढ़कर समयबद्ध सुरक्षा ऑडिट अभियान शुरू करना चाहिए। जिले के प्रत्येक सरकारी और निजी स्कूल की जांच हो। विद्युत उपकरणों और वायरिंग की तकनीकी जांच कराई जाए। जहां कमियां मिलें, उन्हें दूर करने के लिए स्पष्ट समय सीमा तय हो। गंभीर खामियों वाले संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए और जांच की रिपोर्ट भी जिम्मेदार अधिकारियों के स्तर पर सुरक्षित रखी जाए। यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि निरीक्षण केवल रजिस्टरों और दस्तावेजों तक सीमित न रहे। अधिकारी स्कूलों में जाकर वास्तविक स्थिति देखें। बच्चों द्वारा रोज इस्तेमाल की जाने वाली सुविधाओं की सुरक्षा जांचें। वाटर कूलर, पंखे, बिजली के बोर्ड, तार, स्विच, जनरेटर और अन्य विद्युत उपकरणों को केवल देखकर नहीं, बल्कि आवश्यक तकनीकी मानकों के अनुसार जांचा जाए। दिवांश की मौत को यदि व्यवस्था के लिए चेतावनी माना जाए तो शायद उसकी असमय मौत के बाद कोई बड़ा सुधार हो सकता है। लेकिन यदि इसे केवल एक दुर्घटना मानकर फाइल बंद कर दी गई तो यह व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलता होगी। सांध्यदीप का स्पष्ट मत है कि किसी भी बच्चे की सुरक्षा से समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। शिक्षा विभाग को अब जागना होगा। स्कूल प्रबंधन को जवाबदेह बनाना होगा और जिले के प्रत्येक स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था की जांच करनी होगी। क्योंकि अगली बार किसी मां-बाप को यह सुनने का इंतजार नहीं होना चाहिए कि उनका बच्चा स्कूल गया था, लेकिन सुरक्षित घर वापस नहीं लौटा। दिवांश के परिवार को न्याय तभी मिलेगा, जब उसकी मौत केवल एक घटना बनकर न रह जाए, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए मजबूर करे।

मोबाइल टावर पर चढ़ा ग्रामीण, पुलिस की समझाइश के बाद उतरा

हनुमानगढ़। जिले के रोड़ावाली गांव में आज उस समय हड़कंप मच गया, जब एक ग्रामीण अपनी मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। सूचना मिलते ही जंक्शन पुलिस मौके पर पहुंची और हनुमानगढ़ तहसीलदार राजकुमारी ने भी ग्रामीण से समझाइश शुरू की। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीण को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया।

मोबाइल टावर पर ग्रामीण के चढ़ने की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए ग्रामीण से नीचे उतरने की अपील की। इसके बाद तहसीलदार राजकुमारी ने भी मौके पर पहुंचकर उससे बातचीत की और उसकी समस्या सुनने के बाद समझाइश की।

टावर पर चढ़े ग्रामीण की पहचान इन्द्राज के रूप में हुई है। इन्द्राज का आरोप था कि हनुमानगढ़ एसडीएम ने ग्रामीणों की बात सुने बिना ही गांव में रास्ता मंजूर कर दिया। ग्रामीण इसी फैसले से नाराज था और अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गया। इन्द्राज का कहना था कि रास्ते से जुड़े मामले में ग्रामीणों की आपत्तियों और पक्ष को सुना जाना चाहिए था। उसका आरोप है कि ग्रामीणों की सुनवाई किए बिना निर्णय लिया गया, जिसके कारण वह विरोध जताने के लिए टावर पर चढ़ा। मौके पर पहुंचीं तहसीलदार राजकुमारी ने ग्रामीणों से बातचीत की और मामले को लेकर उन्हें कानूनी प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी। तहसीलदार की समझाइश और पुलिस की मौजूदगी में करीब आधे घंटे बाद इन्द्राज मोबाइल टावर से नीचे उतर आया। इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली। ग्रामीण के टावर पर चढ़ने की सूचना के बाद मौके पर काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। इस दौरान सभी की नजर टावर पर चढ़े इन्द्राज पर बनी रही। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति को संभालते हुए किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए लगातार समझाइश का प्रयास किया।

अमित शाह का भाषण नहीं, हमें जवाब चाहिए : राहुल

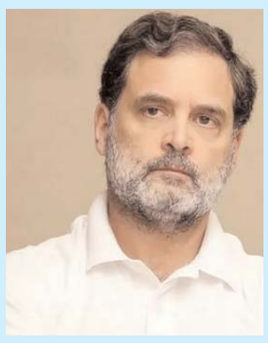

नयी दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से संसद में जवाब देने की मांग करते हुए कहा है कि अब भाषण नहीं, सवालों के जवाब चाहिए।

श्री गांधी ने बुधवार को संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा, श्री शाह ने बच्चों पर गोली चलाने का आदेश दिया था या नहीं। दोनों ही स्थिति में उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। हमें अब अमित शाह का भाषण नहीं चाहिए। हमें जवाब चाहिए। हमारे छात्रों पर गोली किसने चलाई। गोली चलाने का आदेश किसने दिया। किसने एक छात्र की आंख की रोशनी छीनी। कीलों वाली लाठियों के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया।

उन्होंने दावा किया कि यह आदेश गृह मंत्रालय से आया था। उन्होंने सवाल किया कि क्या श्री शाह ने बच्चों पर गोली चलाने का आदेश दिया था या नहीं। श्री गांधी ने कहा कि दोनों ही स्थिति में श्री शाह को इस्तीफा देना चाहिए। विपक्ष के नेता ने कहा, सच ये है कि अमित शाह की इमेज का गुब्बारा फट चुका है। उनके अंदर संसद आने की हिम्मत ही नहीं है। श्री गांधी ने मीडिया से भी सवाल किया कि जब श्री शाह बोलते हैं तो क्या मीडिया उन्हें बीच में रोकता है। उन्होंने पूछा, अमित शाह में ऐसी क्या खास बात है कि पूरा मीडिया चुपचाप खड़ा रहता है।उन्होंने कहा कि जब देश के छात्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और श्री शाह से नहीं डर रहे हैं तो मीडिया को भी उनसे डरना नहीं चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा श्री शाह में संसद आने की हिम्मत ही नहीं है। वह 20 दिनों से गायब हैं। अपने चैंबर में बैठे रहते हैं लेकिन सदन में नहीं आते। उनके काफिले में करीब 30 गाड़ियां चलती हैं, घर के आगे हजारों पुलिस वाले खड़े रहते हैं कि कोई बच्चा न आ जाए। उनकी छवि वाले गुब्बारे की हवा निकल चुकी है।

अनूपगढ़ में मुख्यमंत्री के दौरे पर विरोध के आसार, जिला समाप्ति के मुद्दे पर संगठनों में नाराजगी

श्रीगंगानगर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आगामी 14 अगस्त को श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ उपखण्ड क्षेत्र के प्रस्तावित दौरे को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान अनूपगढ़ को जिला बनाए जाने के बाद अब उसे समाप्त कर दोबारा उपखण्ड मुख्यालय बनाए जाने का मुद्दा एक बार फिर प्रमुखता से उठने की संभावना है। कई संगठनों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की ओर से मुख्यमंत्री के सामने विरोध प्रदर्शन की तैयारी किए जाने की चर्चा है।

स्थानीय स्तर पर सामने आ रही जानकारी के अनुसार भीम आर्मी, कांग्रेस सहित कुछ अन्य संगठन अनूपगढ़ का जिला दर्जा समाप्त किए जाने के फैसले से नाराज हैं और मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान विरोध दर्ज कराने की तैयारी में हैं। विरोध का मुख्य मुद्दा अनूपगढ़ को फिर से जिला बनाए जाने की मांग बताया जा रहा है।

जिला समाप्ति के फैसले से नाराजगी : अनूपगढ़ को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में नया जिला बनाया गया था। जिला बनने के बाद यहां प्रशासनिक ढांचे का विस्तार हुआ और लोगों को उम्मीद थी कि नए जिले के रूप में क्षेत्र का विकास तेज होगा। हालांकि बाद में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार ने पूर्व सरकार द्वारा बनाए गए जिलों की समीक्षा की और अनूपगढ़ को जिला बनाए रखने के बजाय उसका दर्जा समाप्त कर फिर से उपखण्ड मुख्यालय के रूप में कर दिया।

इसी फैसले को लेकर अनूपगढ़ क्षेत्र में लंबे समय से असंतोष की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोगों का तर्क है कि जिला बनने से प्रशासनिक कामकाज के लिए उन्हें अपने ही क्षेत्र में सुविधाएं उपलब्ध होने लगी थीं और कई सरकारी कार्यालय भी स्थापित किए गए थे। जिला समाप्त होने के बाद प्रशासनिक स्तर पर पूर्व व्यवस्था लौटने को लेकर लोगों में नाराजगी है।

मुख्यमंत्री के सामने प्रदर्शन की तैयारी? : मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर अब इस मुद्दे के फिर से गरमाने के आसार हैं। विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान अपनी मांग रखने और विरोध दर्ज कराने की तैयारी कर सकते हैं। हालांकि विरोध का स्वरूप क्या होगा और प्रशासन प्रदर्शनकारियों से किस तरह निपटेगा, यह मुख्यमंत्री के दौरे के समय ही स्पष्ट होगा। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि विरोध करने वाले संगठन मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर अनूपगढ़ को दोबारा जिला बनाने की मांग उठा सकते हैं। यदि संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया जाता है तो पुलिस और प्रशासन के सामने मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी।

भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर भी चर्चा : इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चा यह है कि भाजपा से जुड़े कुछ स्थानीय कार्यकर्ता भी जिला समाप्त किए जाने के फैसले से कथित तौर पर नाराज बताए जा रहे हैं। एक पुलिस अधिकारी ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर ऐसी जानकारी होने की बात कही है। यदि सत्तारूढ़ दल से जुड़े स्थानीय कार्यकर्ता भी इस मुद्दे पर खुलकर सामने आते हैं तो यह सरकार और संगठन दोनों के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थिति हो सकती है। हालांकि इन कार्यकर्ताओं की वास्तविक भूमिका और विरोध में उनकी भागीदारी की आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है।

प्रशासन के सामने सुरक्षा की चुनौती : मुख्यमंत्री का दौरा किसी भी क्षेत्र के लिए प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में किसी भी संभावित विरोध को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी किए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल के आसपास सुरक्षा के साथ-साथ प्रदर्शन की आशंका वाले स्थानों पर भी निगरानी बढ़ाई जा सकती है। प्रशासन के लिए चुनौती यह होगी कि विरोध करने वाले लोगों को अपनी बात रखने का लोकतांत्रिक अधिकार भी मिले और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में किसी प्रकार की अव्यवस्था या कानून-व्यवस्था की स्थिति भी पैदा न हो।

जिला वापस लेने का फैसला बना राजनीतिक मुद्दा : अनूपगढ़ को जिला बनाने और बाद में जिला समाप्त करने का मुद्दा अब केवल प्रशासनिक फैसला नहीं रह गया है। यह क्षेत्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। कांग्रेस इस फैसले को लेकर भाजपा सरकार पर लगातार सवाल उठाती रही है, जबकि जिला बचाने की मांग को लेकर स्थानीय स्तर पर भी अलग-अलग संगठनों की सक्रियता देखी जा रही है।

आगामी मुख्यमंत्री दौरे के दौरान यदि विरोध प्रदर्शन होता है तो इससे यह स्पष्ट संकेत जाएगा कि अनूपगढ़ में जिला समाप्ति का मुद्दा अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री के सामने स्थानीय संगठनों और लोगों की ओर से यह मांग भी रखी जा सकती है कि सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करे।

संपादकीय | सरकार? नीट विवाद पर विपक्ष के सवाल

यह स्थिति तब है, जब राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी गुरुवार को संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू से कहा कि वे गृहमंत्री को सदन में बुलाने के अनुरोध पर विचार करें।पिछले कई दिनों से संसद में जिस तरह का गतिरोध कायम है, दोनों सदनों को बार-बार स्थगित करने की नौबत सामने आ रही है, उसका हल निकालने को लेकर औपचारिक बयानों के अलावा सरकार की ओर से कोई गंभीर कोशिश होती नहीं दिख रही है। सवाल यह है कि अगर एक ही मुद्दे, यानी नीट प्रश्नपत्र लीक पर विरोध जताने वाले प्रदर्शनकारियों के प्रति पुलिस के बेलगाम रवैये पर विपक्षी दल जवाबदेही स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं, तो इससे किस तरह की आपत्ति हो सकती है। यह सही है कि प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे पर विरोध का दायरा व्यापक होते जाने के बाद तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आखिर इस्तीफा दिया। मगर इस मसले पर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थियों पर दिल्ली पुलिस ने जिस तरह बेरहमी से लाठीचार्ज किया, बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं को चोट पहुंची, उसके लिए विपक्षी दल संसद में गृहमंत्री से जवाब की मांग कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस संदर्भ में सरकार की ओर से जिस तरह विपक्ष की इस मांग को प्रकारांतर से खारिज किया जा रहा है, वह साफ तौर पर जवाबदेही से बचने की ही कोशिश है! यह स्थिति तब है, जब राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी गुरुवार को संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू से कहा कि वे गृहमंत्री को सदन में बुलाने के अनुरोध पर विचार करें। मगर इस संदर्भ में कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय विपक्षी

सांसदों के प्रदर्शन को सरकार की ओर से 'ड्रामा' बताया गया। सवाल है कि इस तरह का रुख रखते हुए सरकार क्या यह दावा करने की स्थिति में है कि वह किसी भी मुद्दे पर उठे विवाद का हल संवाद या बातचीत के जरिए निकालने को तैयार है! कहने को किरेन रिजीजू ने परिसीमन के मुद्दे पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बातचीत करके समर्थन मांगा, लेकिन वहां भी प्रस्तावित विधेयकों पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग पर सहमति नहीं बन पा रही है। सरकार अगर किसी भी मुद्दे पर विपक्षी दलों की उपेक्षा कर या उनकी राय को दरकिनार कर एकतरफा तौर पर अपनी मर्जी के मुताबिक कोई हल निकालने के बारे में सोच रही है, तो इसे कैसे देखा जाएगा?

एक तरफ सरकार अपनी सुविधा से संवाद का स्वरूप तय करना चाहती है या फिर इसकी जरूरत को गैर-महत्त्वपूर्ण मानती है, दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत स्पष्ट तौर पर बातचीत करने को ही प्राथमिक और लोकतंत्र का तकाजा मानते हैं। गौरतलब है कि मुंबई में नई पीढ़ी के बच्चों के साथ बातचीत के दौरान भागवत ने यह अहम टिप्पणी की कि 'जेन-जी' देश-विरोधी नहीं हैं और विरोध प्रदर्शन भी संवाद का वैध तरीका तथा लोकतंत्र में सहमति बनाने का एक जरिया है। इस क्रम में अलग-अलग विचार एक साथ आते हैं और चर्चा के बाद आम सहमति बनती है। इस समूचे मसले को इतनी स्पष्टता के साथ भागवत ने जिस तरह देखा है, उसे लोकतंत्र का जीवन-तत्त्व माना जाना चाहिए। इसके बावजूद यह समझना मुश्किल है कि सरकार के भीतर इस मामले में एक विचित्र आग्रह क्यों दिखता है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि नीट प्रश्नपत्र लीक होने के मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के साथ एक अहम बिंदु यह उभरा है कि सरकार की किसी नीति पर सवाल उठाने पर आम जनता के खिलाफ सख्ती बरतने के बजाय जवाबदेही लेने, जवाब देने और संवाद करने से ही लोकतंत्र बचेगा।

बढ़ता तापमान, बढ़ता संकट

यूरोप को धरती का ठंडा क्षेत्र माना जाता है, लेकिन अब वहां भी वनाग्नि की घटनाएं आम हो गई हैं। दक्षिण-पश्चिमी फ्रांस के जंगल इन दिनों भीषण आग से दहक रहे हैं। यहां करीब ढाई लाख लोगों को घर-बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में कई योजनाएं और कार्यक्रम बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें अमल में लाने की गंभीरता कहीं नजर नहीं आती है। विडंबना यह है कि कार्बन उत्सर्जन में जिन देशों का योगदान सबसे कम है, उन्हें ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का खमियाजा सबसे %यादा भुगतना पड़ रहा है। क्लाइमेट इमपेक्ट लेब एक नई अध्ययन रिपोर्ट से भी इस बात की पुष्टि होती है, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक ताप में होने वाली बढ़ोतरी के कारण वर्ष 2050 तक सालाना चार लाख से अधिक लोगों की मौत हो सकती है। इनमें से दस गुना अधिक मौत गरीब देशों में होंगी, क्योंकि वहां लोगों के पास भीषण गर्मी से बचाव के लिए आवश्यक शीतलन सुविधाएं उपलब्ध कराने के संसाधन नहीं हैं।यही नहीं, तापमान बढ़ने से जंगलों में आग की घटनाएं भी लगातार भयावह होती जा रही हैं, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बल्कि मनुष्य के आवासीय इलाकों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।गौरतलब है कि विश्व भर में विकास के नाम पर नए संसाधन विकसित करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। बढ़ते शहरीकरण एवं औद्योगीकरण, वाहनों की संख्या में बेतहाशा इजाफा तथा बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई और जंगलों को नष्ट किए जाने से कार्बन उत्सर्जन का स्तर लगातार बढ़ रहा है।इसमें सबसे बड़ा योगदान विकसित देशों का है, मगर जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में वे निचली कतार में खड़े हैं। बढ़ते तापमान की वजह से जंगल की आग भी विनाशकारी साबित हो रही है।यूरोप को धरती का ठंडा क्षेत्र माना जाता है, लेकिन अब वहां भी वनाग्नि की घटनाएं आम हो गई हैं। दक्षिण-पश्चिमी फ्रांस के जंगल इन दिनों भीषण आग से दहक रहे हैं। यहां करीब ढाई लाख लोगों को घर-बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है।भारत में भी हर साल जंगल की आग से वनस्पतियों का व्यापक नुकसान होता है। ऐसे में जरूरी है कि सुरक्षित भविष्य के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों को लेकर गंभीरता दिखाई जाए और उन पर सख्ती से अमल किया जाए।

आज का कार्टून

सस्ता अमेरिकी अनाज आया तो कौन बचेगा

आज की बदलती वैश्विक भू-राजनीति में युद्ध केवल सीमाओं पर टैंकों और मिसाइलों से नहीं लड़े जाते। इक्कीसवीं सदी का सबसे अमोघ हथियार 'आर्थिक प्रतिबंध', आयात शुल्क और आपूर्ति श्रृंखलाओं की नाकेबंदी बन चुका है। ऐसे अनिश्चित और अस्थिर दौर में किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसकी सेना या विदेशी मुद्रा भंडार से अधिक इस बात से तय होती है कि वह संकट के समय अपने नागरिकों का पेट भरने में कितना आत्मनिर्भर है।

निमिषा सिंह

हाल के दिनों में भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापक कृषि व्यापार समझौते को लेकर सुगबुगाहट तेज हुई है, जिसके साथ ही किसानों का विरोध भी मुखर हो गया है। मुक्त व्यापार के पैरोकार इसे आर्थिक उदारीकरण का अगला चरण बता रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत, उत्पादन लागत और वैश्विक सामरिक उदाहरणों का विश्लेषण स्पष्ट करता है कि कृषि को महज एक 'व्यापारिक वस्तु' मानना भारत के लिए एक आत्मघाती रणनीतिक भूल हो सकती है।

वर्तमान विरोध के संदर्भ को समझने के लिए साल 2026 के ऐतिहासिक वैश्विक व्यापार समझौतों पर गौर करना जरूरी है। इन समझौतों का कोई विरोध इसलिए नहीं हुआ कि भारत ने कृषि और डेयरी क्षेत्र को अपनी 'रेड लाइन' मानकर पूरी तरह सुरक्षित रखा था। जनवरी 2026 के 'मदर ऑफ ऑल डील्स' यानी भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में यूरोप ने नब्बे फीसद भारतीय कृषि उत्पादों को शुल्क मुक्त कर दिया, लेकिन भारी दबाव के बावजूद भारत ने अपने डेयरी उत्पादों और मुख्य खाद्यान्नों को सुरक्षित रखा तथा अमेरिकी जीएम फसलों पर प्रतिबंध जारी रखा।

इसी तरह, फरवरी 2026 के भारत-अमेरिका समझौते ने भारत को तीस ट्रिलियन डॉलर के विशाल अमेरिकी बाजार तक तरजीही पहुंच दिलाई, लेकिन इसमें भी संवेदनशील कृषि क्षेत्र और डेयरी को बाहर रखा गया था। जुलाई 2026 के भारत-ब्रिटेन सीईटीए के तहत ब्रिटेन ने निन्यानबे फीसद भारतीय उत्पादों से शुल्क हटा लिया, लेकिन यहां भी भारत का कृषि और डेयरी क्षेत्र समझौते के दायरे से बाहर रहा। न्यूजीलैंड के साथ हुए समझौते में भी भारत ने अपने मजबूत डेयरी उद्योग को पूरी तरह संरक्षित रखा और केवल अत्याधुनिक कृषि तकनीक के बदले कीवी और सेब जैसे फलों पर आंशिक छूट दी।

पूर्व के इन समझौतों पर कोई हंगामा नहीं हुआ, लेकिन भारत-अमेरिका के बीच संभावित 'व्यापक कृषि व्यापार समझौते' पर आशंका इसलिए है कि अब दबाव उन सीमा रेखाओं को पार करने का है। अमेरिका अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों, मक्का, सोयाबीन, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों के लिए भारतीय बाजार को पूरी तरह खोलने का दबाव बना रहा है।

असमान ध्रुव

भारत और अमेरिका की कृषि पद्धति में जमीन-आसमान का अंतर है। अगर यह बाजार खुलता है, तो यह दो असमान व्यवस्थाओं के बीच का ऐसा मुकाबला होगा, जिसमें भारतीय किसानों का हारना तय है। भारत में छियासी फीसद किसान छोटे और सीमांत हैं, जिनके पास दो हेक्टेयर से कम जमीन है और वे मानसून, महंगे डीजल तथा सीमित पूंजी के सहारे खेती करते हैं। इसके विपरीत, अमेरिका में खेती एक कॉरपोरेट उद्योग है, जहां हजारों एकड़ के खेत, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन और जीपीएस आधारित मशीनों का उपयोग होता है।

दोनों देशों के बीच उत्पादकता का भारी अंतर है। उदाहरण के लिए मक्का, जो आज पोल्ट्री, एथेनॉल और खाद्य प्रसंस्करण की रीढ़ है, अमेरिका में एक एकड़ में एक सौ दस से एक सौ बीस क्विंटल पैदा होता है, जबकि भारत में यह औसत मात्र पंद्रह से बीस क्विंटल प्रति एकड़ है। इतनी कम प्रति इकाई लागत के साथ, अमेरिकी कॉरपोरेट आसानी से भारतीय बाजार में अपना सामान पेश कर सकता है, जिसके सामने दो एकड़ वाला भारतीय किसान कभी नहीं टिक पाएगा।

मुक्त व्यापार को लेकर एक भ्रम यह फैलाया जाता है कि अमेरिका में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी नहीं है और वहां किसान बाजार के भरोसे हैं। सच इसके बिल्कुल उलट है। भारत में किसान आज भी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश (सी2 पचास फीसद) के आधार पर एमएसपी की कानूनी गारंटी मांग रहा है, जबकि सरकार ए2एफएल के आधार पर नीतियां तय करती है। वहीं, अमेरिका में किसानों को बचाने के लिए एक अभेद्य आय सुरक्षा चक्र है। 'प्राइस लॉस कवरेज' और 'एग्रीकल्चर रिस्क कवरेज' जैसे कार्यक्रमों के तहत बाजार मूल्य गिरने पर अमेरिकी सरकार किसानों को भारी सब्सिडी और सीधे नकद नुकसान की भरपाई करती है। आयात से उपभोक्ताओं को सस्ता सामान मिलने का तर्क कृषि के संदर्भ में सबसे घातक है। शुरुआत में सस्ता अमेरिकी मक्का, सोयाबीन या खाद्य तेल बाजार में आएगा और प्रतिस्पर्धा न कर पाने के कारण भारतीय किसान घाटे में जाकर इन फसलों को उगाना बंद कर देंगे। कृषि कोई कारखाना नहीं है कि बटन दबाया और उत्पादन फिर शुरू हो गया। एक बार अगर किसान ने खाद्यान्न उगाना छोड़ दिया और देश का बीज चक्र, बुनियादी ढांचा और ज्ञान नष्ट हो गया, तो उसे दोबारा खड़ा करने में करीब तीस साल लग जाएंगे। स्थानीय उत्पादन खत्म होते ही विदेशी एकाधिकारवादी मनमानी कीमतें वसूलेंगे, जिससे न किसान बचेगा और न ही उपभोक्ता।

संवेदनशील पहलू

डेयरी और जीएम फसलों का संकट भी इस समझौते का एक बेहद संवेदनशील पहलू है। भारत का डेयरी क्षेत्र आठ करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों की आय का स्रोत है, जहां अधिकांश दूध उत्पादन दो-तीन पशुओं वाले छोटे किसानों द्वारा होता है। दूसरी ओर, अमेरिका में बड़े कॉरपोरेट डेयरी फार्म भारी सब्सिडी और बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था के दम पर बेहद सस्ता दूध पाउडर बनाते हैं, जिनके आयात से भारतीय किसानों को दूध का सही दाम नहीं मिल सकेगा।

इसके साथ ही, अमेरिका लंबे समय से जीएम मक्का और जीएम सोयाबीन के लिए बाजार पहुंच की मांग कर रहा है। भारत अब तक खाद्य जीएम फसलों पर सतर्क रहा है, क्योंकि यह केवल व्यापार का नहीं, बल्कि जैव सुरक्षा, पर्यावरण, बीज संप्रभुता और उपभोक्ता विश्वास का प्रश्न है।

संरक्षण के समांतर

सरकार का दावा है कि इस व्यापार समझौते में भारतीय किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। सरकार के अनुसार, चाय, कॉफी, मसाले और नारियल जैसे कृषि उत्पादों को अमेरिकी बाजार में कम या 'शून्य शुल्क' का लाभ मिलेगा। भारतीय मसाले, बासमती चावल, बागवानी उत्पाद, प्रसंस्कृत खाद्य और जैविक उत्पादों की वैश्विक मांग लगातार बढ़ रही है। अगर गुणवत्ता मानकों और 'कोल्ड चेन' को मजबूत किया जाए, तो भारतीय किसान अंतरराष्ट्रीय बाजार से बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। भारत की अधिकांश व्यापार संधियों का अनुभव भी बताता है कि सरकार ने संवेदनशील क्षेत्रों को संरक्षण देते हुए अन्य क्षेत्रों में बाजार खोलने की रणनीति अपनाई है।

अमेरिका के साथ वार्ता कहीं अधिक जटिल है, क्योंकि यहां कृषि सब्सिडी, डेयरी, जीएम फसलें, बाजार पहुंच और गैर-शुल्क बाधाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं। अंतिम समझौते का प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत किन उत्पादों पर शुल्क संरक्षण बनाए रखता है और किस प्रकार के सुरक्षा मानक तथा आयात कोटा लागू करता है। सरकार के सामने यह सबसे बड़ी परीक्षा है कि किसी भी समझौते का मूल्यांकन केवल आयात-निर्यात के आंकड़ों पर नहीं, बल्कि इस कसौटी पर हो कि क्या इससे भारत का अन्नदाता मजबूत होगा, क्या भारतीय उपभोक्ता सुरक्षित रहेगा और क्या हमारी खाद्य संप्रभुता अक्षुण्ण रहेगी। अगर इसका उत्तर स्पष्ट नहीं है, तो अमेरिका के साथ किसी भी दबाव वाली कृषि सौदेबाजी से पीछे हटना ही हमारा राष्ट्रधर्म होगा।

संसद ठप, 'चढ़ावा चोरी' का शोर

हाल में सबसे मजेदार कहानी निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बनाई। वे सभी चैनलों के हीरो रहे, सिद्ध हुआ कि खुद को खबरों में बनाए रखना वे बखूबी जानते हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू राहुल गांधी से मिलकर कहते हैं कि मान जाओ और संसद चलने दो ज महत्त्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा करो, लेकिन राहुल हैं कि मानते ही नहीं। वे अड़े हैं कि जब तक केंद्रीय गृहमंत्री 'विद्यार्थियों पर पैलेट गन चलाने' की घटना पर वक्तव्य नहीं दे देते, तब तक संसद नहीं चलने देंगे।

सुधीश पचौरी

फर्क इतना ही है कि पहले वे गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े थे, अब बयान पर अड़े हैं। एक तरफ सत्तापक्ष की 'जिद', तो दूसरी ओर विपक्ष की 'जिद' संसद के कामकाज को 'स्थगित' कराती रहती है। हर रोज सदन में हंगामे के बाद विपक्ष के ज्यादातर दल संसद परिसर में गृहमंत्री के बयान की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हैं। जो बहस संसद में नहीं हो पाती, वो शाम को चैनलों पर होती है, लेकिन वहां भी कई बार बहस 'तू-तू, मैं-मैं' में बदल जाती है। फिर एंकर की ओर से बीच-बचाव किया जाता है। कई बार प्रवक्ता नाराज होकर बहस बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। हाल में सबसे मजेदार कहानी निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बनाई। वे सभी चैनलों के हीरो रहे, सिद्ध हुआ कि खुद को खबरों में बनाए रखना वे बखूबी जानते हैं। वे एक दिन भगवा वस्त्र पहनकर साधु के भेष में संसद पहुंचे और बाहर 'मकर द्वार' के पास बैठ गए। वे वहां 'यज्ञ' करने का 'नाटक' करने लगे और नाटकीय रूप में कुछ मंत्र उच्चारित करते दिखे। उनके चारों ओर घेरा बनाकर खड़े विपक्ष के सांसद बारी-बारी से आकर उनके डिब्बे में चढ़ावा चढ़ाते दिखे। यही नहीं, आजू-बाजू खड़े सांसद 'चंदा चोर-चंदा चोर' के नारे लगाते नजर आए। फिर पप्पू यादव ने जब चंदे के डिब्बे को चुराकर भागने का नाटक किया, तो वहां मौजूद सांसद उन्हें पकड़ने की कोशिश करते दिखे। यह 'चढ़ावा चोरी कांड' की एक 'पैरोडी' थी, जिसकी पटकथा खराब बताई गई, लेकिन पप्पू यादव और अन्य विपक्षी सांसद इस 'नुक्कड़ नाटक' का आनंद लेते नजर आए। 'चढ़ावा चोरी' का यह नाटक कुछ सांसदों के लिए भले मजेदार रहा

हो, मगर सत्तापक्ष और उसके समर्थकों ने इस पर सवालों की बौछार कर दी। चैनलों पर इस नाटक का प्रसारण देख देश का 'साधु-संत समाज' पप्पू यादव के पीछे पड़ गया और उनका जमकर विरोध किया। भाजपा प्रवक्ताओं ने भी इसे 'साधु-संतों का अपमान' बताया। एक चर्चक ने तो इस तरह के नुक्कड़ नाटक को संसद के बाहर करने पर सवाल उठाते हुए इसे 'साधु-संतों' के खिलाफ लोगों को 'उकसाने' वाला करार दिया। इसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान पप्पू यादव पर हमले की कोशिश भी हुई, हालांकि पुलिस ने बीच-बचाव कर स्थिति को संभाल लिया।

चुनाव में 'किसका फायदा होगा और किसका नुकसान'

मगर चैनल चर्चा में यह मुद्दा जल्द ही उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में 'किसका फायदा होगा और किसका नुकसान' वाले मुद्दे में बदल गयाज। ऐसे मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत कुछ कहता नजर आया। इस सप्ताह उन्होंने 'पीडीए' की एकदम 'नई व्याख्या' करके सबको चकित कर दिया। उन्होंने बताया कि 'पीडीए' का मतलब 'पंडित है'ज। एक चर्चक ने साफ किया कि इस 'स्किट' ने स्पष्ट कर दिया कि उत्तर प्रदेश में जीतने के लिए सपा वाले इस बार 'सवर्ण जातियों', खासकर 'ब्राह्मणों' को अपना नया 'वोट बैंक' बनाने के चक्कर में हैं। इस बीच, झारखंड के रांची में राज्य की 'परीक्षा व्यवस्था' में पैदा हुई गड़बड़ियों में सुधार करने की मांग को लेकर कई दिन से भूख हड़ताल कर रहे कुछ विद्यार्थी बार-बार खबर बनते रहे। चर्चा में कई चर्चक 'जंतर-मंतर ब्रांड' जेन-जी के प्रदर्शन और उनके 'खानपान' की तुलना 'रांची में प्रदर्शन' कर रहे युवाओं के 'सादे खानपान' से करते नजर आए। एक चैनल तो 'जंतर-मंतर' के जेन-जी की 'पांच सितारा जीवनशैली' के पीछे ही पड़ गया और रांची में भूख हड़ताल पर बैठे विद्यार्थियों के प्रति अपनी पूरी हमदर्दी एवं संवेदना जताता रहा। साथ ही जंतर-मंतर वाली जेन-जी की ओर से रांची में भूख हड़ताल करने वालों को लेकर अपनाई गई चुप्पी पर सवाल उठाता रहा। फिर एक एंकर ने रहस्य खोला कि 'काकरोच जनता पार्टी' की ओर से बनाई गई 'आठ सदस्यों की टीम' में एक भी 'जेन-जी विद्यार्थी' को शामिल नहीं किया गया है। इसे देख कुछ जेन-जी 'काकरोच पार्टी' से मांग करने लगे कि हमने भी लाठी खाई है, सबकी राय लेकर सबको पार्टी से जोड़ें। फिर आया तेरह साल पहले 'बलात्कार' के आरोपित तरुण तेजपाल को 'दस साल के कारावास' की सजा देने वाला मुंबई हाई कोर्ट का फैसला। इस पर यों तो सभी चैनलों में चर्चा रही, लेकिन जिस तरह से एक एंकर ने तेजपाल तथा उसके समर्थन में आईं मशहूर हस्तियों और नामचीन नेताओं के पुराने बयानों की खबर ली, वह देखते ही बनती थी। एक वकील को तो एंकर ने इस तरह लाजवाब किया कि वह नाराज होकर बहस से बाहर हो गईं।

बारिश में पशुओं की देखभाल

बारिश के मौसम में बीमार पशु द्वारा मिट्टी और पानी भी संक्रमित हो जाते हैं जिस के संपर्क में आने से स्वस्थ पशुओं के संक्रमित होने की सम्भावना बड़ जाती है। इस लिये रोगी पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखें। इस मौसम में पशुओं में होने वाले प्रमुख संक्रामक रोग जैसे गलघोटू, लंगड़ा बुखार, खुरपका मुँहपका, न्यूमोनिया आदि हैं। परजीवी रोगों में बबेसिओसिस, थैलेरिओसिस आदि प्रमुख रोग हैं। पशुओं में होने वाले संक्रामक रोग जैसे खुरपका मुँहपका, गलघोटू तथा लंगड़ा बुखार प्रमुखता से बरसात के दिनों में गौवंश को प्रभावित करते है तथा कई बार पशुओं की जान भी चली जाती है। इन रोगों से बचाव हेतु बारिश से पहले टीकाकरण करना आवश्यक है टीकाकरण की जानकारी नीचे दी गई है ।

बारिश से पहले पशुओं में टीकाकरण

टीकाकरण के द्वारा विश्व में करोड़ों पशुओं में विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाव संभव है इस तरह पशुपालकों अपने पशुओं का उचित टीकाकरण पशु चिकित्सक की सलाह पर शुरुआत में ही करें तथा प्रति वर्ष पुन: टीकाकरण दोहराना चाहिए। गाय एवं भैंसों में खुरपका मुँहपका, गलघोंटू, टंगिया रोग आदि का टीका बारिश से पहले लगाया जाता है। भेड़ और बकरियों में भी मानसून की शुरुआत में पीपीआर और गलघोंटू का टीका लगाया जाता है। टीकाकरण की विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है

परजीवियों का प्रकोप

बारिश के मौसम में प्राय: परजीवियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती हैं। जिससे पशुओं को शारीरिक व्याधियों का सामना करना पड़ता हैं। परजीवी प्राय: दो प्रकार के होते हैं –

- **अन्त: जीवी** – जैसे पेट के कीड़े, कृमि आदि
- **बाह्य जीवी** – चीचड़, मेंज, जूं आदि

लक्षण – रोगग्रसित पशु में सुस्ती, कमजोरी, अनीमिया (खून की कमी) एवं दूध में कमी देखने को मिलती है। पशु को पाचन प्रक्रिया में शिकायत रहती है जिससे पेट में दर्द और पतला गोबर आता है।

उपचार– पशुचिकत्सक की सलाह से पशुओं को उनके वजन के अनुसार परजीवीनाशक दवा नियमित रूप से दो बार पिलायें।

बचाव– बारिश के मौसम में पशुओं को तालाब के किनारे न लेकर जाएं। इसके साथ-साथ तालाब की किनारों वाली घास न खिलाएं, क्योंकि ये घास कीड़ों के लार्वा से ग्रस्त होती हैं। जो कि पेट में जाकर कीड़े बन जाते हैं और अनेक विकार उत्पन्न करते हैं।

खाज-खुजली

बारिश के मौसम में अक्सर पशुओं में खाज-खुजली की शिकायत होती है इसका मुख्य कारण पशुशाला में गंदगी का होना है। इस रोग में पशु की त्वचा पर अत्यंत खुजलाहट होती है, जिसकी वजह से त्वचा मोटी होकर मुरझा जाती है एवं पशु के खुजली करने पर त्वचा छिल जाती है और उस जगह के सारे बाल झड़ जाते हैं। कभी-कभी इन जगह पर जीवाणुओं के संक्रमण से दुर्गन्ध भी आती है।

चीचड़: बारिश के मौसम में अक्सर पशुओं में चीचड़ लग जाते हैं ये चीचड़ पशु का खून चूसते हैं जिससे खून की कमी हो जाती है तथा कई प्रकार के रोग भी फैलाते हैं जैसे बबेसिओसिस, थैलेरिओसिस आदि।

उपचार– पशुचिकित्सक की सलाह से कीटनाशक दवा को पशु के ऊपर लगायें तथा पशुशाला में भी छिड़काव करायें।

बारिश के मौसम में पशुओं के रखरखाव में सावधानियां

उपरोक्त बीमारियों को ध्यान में रखने के साथ-साथ पशुपालकों को वर्षा ऋतु में पशु प्रबंधन सम्बंधी बातों पर भी गौर करें जो कि निम्नलिखित हैं।

- बारिश के पहले पशुओं के पशुशाला की छत की मरम्मत कर दें जिससे बारिश का पानी ना टपके।
- पशुशाला की खिड़कियाँ खुली रखें तथा गर्मी एवं उमस से बचने के लिये पंखों का उपयोग करें।
- इस मौसम में साफसफाई का ख़ास खयाल रखें एवं पानी को एक जगह पर एकत्रित नहीं होने दें जिससे मच्छर ना हों और परजीवी संक्रमण रोका जा सके।
- पशुशाला में पशु के मलमूत्र के निकासी का भी उचित प्रबंध हो। पशुशाला को दिन में एक बार फिनाइल के घोल से अवश्य साफ करें, जिससे बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया कम हो सकें।
- बाड़े में और उसके आसपास कचरा और गंदगी इकट्ठा ना होने दें और उसके निकास की उचित व्यवस्था हो। नियमित अंतराल पर कीटनाशक को भी छिड़कें।
- जानवरों को ज्यादा शारीरिक थकावट ना होने दें और बार-बार धूप में ना लाएं।
- बारिश के मौसम में पशुओं को बाहर चरने के लिए नहीं भेजें क्योंकि बारिश के मौसम में गीली घास पर कई तरह के कीड़े होते हैं जो पशुओं के पेट में चले जाते हैं और शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं।
- पशु को खेतों के समीप गड्ढे या जोहड़ का पानी पिलाने से परहेज करें क्योंकि इस दौरान किसान खेतों में खरपतवार एवं कीटनाशक का इस्तमाल करते हैं जो कि रिसकर इनमें आ जाता है। कोशिश करें की पशु को बाल्टी से साफएवं ताजा पानी पिलाएं।
- दाने का भंडारण नमी रहित जगह पर करें और ध्यान दें कि इस मौसम में दाने को 15 दिन से अधिक भंडार न करें।

धान की उन्नत उत्पादन तकनीक

आज के समय में धान की उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता है, यह तभी सम्भव हो सकता है जब धान उत्पादन हेतु उन्नत उत्पादन तकनीक अपनायी जाये।

भूमि की तैयारी

धान की फसल के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 2-3 जुताइयां कल्टीवेटर से करके खेत तैयार करें। साथ ही खेत की मजबूत मेड़बन्दी कर दें जिससे कि वर्षा का पानी अधिक समय तक संचित किया जा सके। रोपाई से पूर्व खेत में पानी भरकर जुताई कर दें, साथ ही जुताई के समय खेत को समतल कर लें।

बीज की मात्रा

एक हेक्टेयर क्षेत्र में रोपाई हेतु साधारण भूमि में 30 किग्रा महीन धान का बीज, 35 किग्रा मध्यम धान का बीज तथा 40 किग्रा मोटे धान का बीज पौध तैयार करने हेतु पर्याप्त होता है। ऊसर भूमि में बीज की मात्रा सवागुनी अधिक लगती है।

नर्सरी का क्षेत्रफल

सामान्य परिस्थिति में एक हेक्टेयर क्षेत्र की रोपाई हेतु 800-1000 वर्गमीटर क्षेत्र की नर्सरी पर्याप्त होती है।

रोपाई हेतु पौधे की आयु

धान की रोपाई हेतु 3-4 सप्ताह क पौध लगाना अच्छा रहता है। इस आयु तक पौध में 4-5 पत्तियां निकल आती हैं। लम्बे जीवनकाल हेतु एक सप्ताह की पौध लगायें। इस प्रकार 90-100 दिन की प्रजातियों हेतु 3-4 सप्ताह तथा 150 दिन की प्रजातियों हेतु एक माह की पौध लगाना श्रेयष्कर होता है।

उचित गहराई व दूरी पर रोपाई

बौनी प्रजातियों की पौध की रोपाई 3-4 सेमी से अधिक की गहराई पर नहीं करें अन्यथा कल्ले कम निकलते हैं और उपज प्रभावित होती है। साधारण मृदाओं में पंक्ति से पंक्ति व पौधे से पौधे की दूरी 20310 सेमी तक उर्वर मृदा में 20315 सेमी रखें। एक स्थान पर 2-3 पौधे लगायें। यदि रोपाई में देर हो जाए तो एक स्थान पर 3-4 पौध लगायें तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 5 सेमी कम कर दें। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि प्रतिवर्ग मीटर क्षेत्रफल में 50 टिल अवश्य हो, ऊसर तथा देर से रोपाई की स्थिति में 65-70 टिल हो।

खाद एवं उर्वरक

खाद एवं उर्वरक का प्रयोग मृदा परीक्षण की संस्तुतियों के आधार पर ही करें। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए कम्पोस्ट खाद 10-15 टन प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। धान की फसल में हरी खाद के रूप में ढैंचा तथा सनई का प्रयोग काफी लाभकारी पाया गया है। सिंचित दशा में अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के लिए 120 किग्रा नाइट्रोजन 60 किग्रा. फास्फोरस तथा 60 किग्रा पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। देशी प्रजातियों के लिए 60 किग्रा नाइट्रोजन, 30 किग्रा फास्फोरस एवं 30 किग्रा पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। अन्य तत्वों की पूर्ति के लिए 30-40 किग्रा गन्धक एवं 20-25 किग्रा जिंक सल्फेट तथा सूक्ष्म पोषक तत्व मिश्रण 20-25 किग्रा प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें।

खाद एवं उर्वरक प्रयोग करने की विधि

नाइट्रोजन की आधी मात्रा फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा रोपाई से पूर्व तथा नाइट्रोजन की शेष मात्रा बराबर-बराबर दो भागों में कल्ले फूटते समय तथा बाली बनने की अवस्था में टापड्रेसिंग के रूप में प्रयोग करें।

जल प्रबंधन

सिंचाई की पर्याप्त सविधा रहने पर रोपाई के एक सप्ताह तक कल्ले फूटते समय, बाली निकलते समय, फूल खिलते समय तथा दाना भरते समय खेत में 4-5 सेमी पानी रहना लाभकारी रहता है। फूल खिलने की अवस्था पानी के लिए अति संवेदनशील है। कल्ले निकलते समय अंतिम 4-5 दिनों के लिए खेत से पानी निकाल देना उचित रहता है। अनुसंधानों के आधार पर यह पाया गया है कि धान की अधिक उपज पाने के लिए लगातार खेत में पानी भरा रहना आवश्यक नहीं है इसके लिए खेत की सतह से पानी अदृश्य होने के एक दिन बाद 5-7 सेमी सिंचाई करना उपयुक्त होता है ।

खरपतवार नियंत्रण

रोपाई के 4-5 दिनों के अन्दर प्रति हेक्टेयर ब्यूटाक्लोर 50 प्रतिशत ई.सी. 2.5 लीटर अथवा प्रिटलाक्लोर 50 प्रतिशत ई.सी. 1.25 लीटर का प्रयोग 3-4 सेमी खेत में भरे पानी की अवस्था में प्रयोग करें। रोपाई के 15-20 दिन बाद खरपतवार नियंत्रण हेतु विसपायरी बैक सोडियम 10 प्रतिशत एस.सी. 0.20 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में नमी की स्थिति में 500 लीटर पानी में घोलकर फ्लेटफेन नॉजिल से छिड़काव करें।

पशुओं के लिए पौष्टिक आहार अजोला

अजोला तेजी से बड़ने वाली एक प्रकार की जलीय फर्न है, जो पानी की सतह पर तैरती रहती है। धान की फसल में नील हरित काई की तरह अजोला को भी हरी खाद के रूप में उगाया जाता है और कई बार यह खेत में प्राकृतिक रूप से भी उग जाता है। अजोला की सतह पर नील हरित शैवाल सहजैविक के रूप में विध्यमान होता है। इस नील हरित शैवाल को एनाबिना एजोली के नाम से जाना जाता है जो कि वातावरण से नत्रजन के स्थायी करण के लिए उत्तरदायी रहता है। देखने में यह शैवाल से मिलती-जुलती है और आमतौर पर उथले पानी में अथवा धान के खेत में पाई जाती है।

अजोला का उत्पादन

अजोला का उत्पादन बहुत ही आसान है। सबसे पहले किसी भी छायादार स्थान पर 2 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा तथा 30 सेमी. गहरा गड्ढा खोदा जाता है। पानी के रिसाव को रोकने के लिए इस गड्ढे को प्लास्टिक शीट से ढंक देते हैं। जहां तक संभव हो पराबैंगनी किरणरोधी प्लास्टिक सीट का प्रयोग करें। प्लास्टिक सीट सिलपोलीन एक पॉलीथिन तारपोलीन है जो कि प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के

लिए प्रतिरोधी क्षमता रखती है। सीमेंट की टंकी में भी एजोला उगाया जा सकता है। सीमेंट की टंकी में प्लास्टिक सीट बिछाने की आवश्यकता नहीं हैं।

अब गड्ढे में 10-15 किग्रा. मिट्टी फैलाना है। इसके अलावा 2 किग्रा. गोबर एवं 30 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट 10 लीटर पानी में मिलाकर गड्ढे में डाल देना है। पानी का स्तर 10-12 सेमी. तक हो। अब 500-1000 ग्राम अजोला कल्चर गड्ढे के पानी में डाल देते हैं। पहली बार एजोला का कल्चर किसी प्रतिष्ठित संस्थान मसलन प्रदेश में स्थित कृषि विश्वविद्यालयों के मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग से क्रय करें। अजोला बहुत तेजी से बड़ता है और 10-15 दिन के अंदर पूरे गड्ढे को ढंक लेता है। इसके बाद से 1000-1500 ग्राम अजोला प्रतिदिन छलनी या बांस की टोकरी से पानी के ऊपर से बाहर निकाला जा सकता है।

प्रत्येक सप्ताह एक बार 20 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 1 किलो गोबर गड्ढे में डालने से अजोला तेजी से विकसित होता है। साफ पानी से धो लेने के बाद 1.5 से 2 किग्रा. अजोला नियमित आहार के साथ पशुओं को खिलाया जा सकता है।

अजोला उत्पादन में सावधानियां

- अजोला की तेज बढ़वार और उत्पादन के लिए इसे प्रतिदिन उपयोग हेतु (लगभग 200 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से) बाहर निकाला जाना आवश्यक हैं।
- समय-समय पर गड्ढे में गोबर एवं सिंगल सुपर फॉस्फेट डालते रहें जिससे अजोला फर्न तीव्र गति से विकसित होता रहे।
- प्रति माह एक बार अजोला तैयार करने वाले गड्ढे या टंकी की लगभग 5 किलो मिट्टी को ताजा मिट्टी से बदलें जिससे नत्रजन की अधिकता या अन्य खनिजों की कमी होने से बचाया जा सके।
- अजोला तैयार करने की टंकी के पानी के पीएच मान का समय-समय पर परीक्षण करते रहें। इसका पीएच मान 5.5-7.0 के मध्य होना उत्तम रहता है।
- प्रति 10 दिनों के अंतराल में, एक बार अजोला तैयार करने की टंकी या गड्ढे से 25-30 प्रतिशत पानी ताजे पानी से बदल दें जिससे नाइट्रोजन की अधिकता से बचायें।
- प्रति 6 माह के अंतराल में, एक बार अजोला तैयार करने की टंकी या गड्ढे को पूरी तरह खाली कर साफ कर नये सिरे से मिट्टी, गोबर, पानी एवं अजोला कल्चर डालें।

पशुओं को अजोला चारा खिलाने के फायदे

अजोला से पशुओं में कैल्शियम, फॉस्फोरस, लोहे की आवश्यकता की पूर्ति होती है जिससे पशुओं का शारिरिक विकास अच्छा है। अत: इसकी संरचना इसे अत्यंत पौष्टिक एवं असरकारक आदर्श पशु आहार बनाती है। यह गाय, भैंस, भेड़, बकरियों, मुर्गियों आदि के लिए एक आदर्श चारा सिद्ध हो रहा है। दुधारू पशुओं पर किए गए प्रयोगों से साबित होता है कि जब पशुओं को उनके दैनिक आहार के साथ 1.5 से 2 किग्रा. अजोला प्रतिदिन दिया जाता है तो दुग्ध उत्पादन में 15-20 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गयी है। इसके साथ इसे खाने वाली गाय-भैसों की दूध की गुणवत्ता भी पहले से बेहतर हो जाती है। प्रदेश में मुर्गी पालन व्यवसाय भी बहुतायत में प्रचलित है। यह बेहद सुपाच्य होता है और यह मुर्गियों का भी पसंदीदा आहार है। कुक्कुट आहार के रूप में अजोला का प्रयोग करने पर ब्रायलर पक्षियों के भार में वृद्धि तथा अण्डा उत्पादन में भी वृद्धि पाई जाती है। यह मुर्गी पालन करने वाले व्यवसाइयों के लिए बेहद लाभकारी चारा सिद्ध हो रहा है। यही नहीं अजोला को भेड़-बकरियों, सूकरों एवं खरगोश, बतखों के आहार के रूप में भी बखूबी इस्तेमाल किया जा सकता है।

कृषि महाविद्यालय भवन को चुनाव के लिए एक्वायर करने के विरोध में कांग्रेस और विद्यार्थियों का प्रदर्शन

हनुमानगढ़। आगामी चुनावों के लिए कृषि महाविद्यालय के भवन को जिला प्रशासन द्वारा अधिग्रहित किए जाने और विद्यार्थियों को पुराने जर्जर भवन में शिफ्ट किए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं विद्यार्थियों ने आज कृषि महाविद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने महाविद्यालय भवन पर ताला जड़ दिया और स्टाफ को अंदर बंद कर धरना शुरू कर दिया।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांग की कि विद्यार्थियों को किसी भी स्थिति में जर्जर भवन में स्थानांतरित नहीं किया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मौजूदा भवन में विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जबकि पुराने भवन की स्थिति चिंताजनक है।

धरने को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनीष मक्कासर ने कहा कि पुराने भवन में करीब 50 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि कृषि महाविद्यालय में वर्तमान में लगभग 280 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। ऐसे में इतने अधिक विद्यार्थियों को पुराने भवन में शिफ्ट करना उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा।

उन्होंने कहा कि पुराना भवन जर्जर स्थिति में है और उसकी हालत को देखते हुए वहां विद्यार्थियों को बैठाना किसी भी समय बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि चुनावी व्यवस्था के लिए महाविद्यालय भवन को अधिग्रहित करने से पहले विद्यार्थियों की सुरक्षा और पढ़ाई की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाए।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन को चुनावी तैयारियों के साथ-साथ शिक्षा व्यवस्था को भी ध्यान में रखना चाहिए। विद्यार्थियों को ऐसे भवन में भेजना उचित नहीं है जहां पर्याक्षमता और सुरक्षित आधारभूत ढांचा उपलब्ध नहीं है।

वहीं प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों ने भी महाविद्यालय प्रशासन और जिला प्रशासन के समक्ष कई मांगें रखीं। विद्यार्थियों का कहना था कि यदि वर्तमान भवन को चुनाव के लिए लिया जाता है तो विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक रूप से ऐसा भवन उपलब्ध कराया जाना चाहिए जो सुरक्षित हो और जिसमें सभी विद्यार्थियों के बैठने तथा पढ़ाई की पर्याव्यवस्था हो।

देशभक्ति संगीत का कार्यक्रम स्वरांजलि 16 अगस्त को

8

श्रीगंगानगर। शहर में कला और संस्कृति की धरोहर को संजोए रखने वाली प्रतिष्ठित संस्था राष्ट्रीय कला मंदिर और शहर की पहली महिला कलाकारों की नवगठित संस्था 'सुरसखी' के संयुक्त तत्वावधान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम 'स्वरांजलि' का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 16 अगस्त को शाम 6.31 बजे रोहित उद्योग परिसर स्थित चौधरी रामजस सदन (ऑडिटोरियम) में होगा।

राष्ट्रीय कला मंदिर के अध्यक्ष वीरेंद्र बैद ने बताया कि संस्था डडलगभग 75 वर्षों से गीत-संगीत और नृत्य को समर्पित रही है। यह मंच वर्षों से कलाकारों को प्रोत्साहित करने, नई प्रतिभाओं को अवसर देने तथा कला एवं संस्कृति के संरक्षण-संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। शहर की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत बनाने में राष्ट्रीय कला मंदिर का योगदान सराहनीय रहा है।

उन्होंने बताया कि स्वरांजली कार्यक्रम की विशेष बात यह है कि इसमें शहर की पहली महिला कलाकारों की संस्था 'सुरसखी' सह-आयोजक के रूप में शामिल है। डॉ. रजनी अग्र पहल पर उनके संगीत-प्रेमी मित्रों के साथ मात्र आठ महिलाओं से सुरसखी की शुरुआत हुई थी। संस्था के गठन में रिद्धम गुरु सुनील मौर्य का अहम योगदान रहा। कुछ ही दिनों में यह छोटा समूह अनेक प्रतिभाशाली महिलाओं के बड़े कारवाँ में बदल चुका है।

डॉ. रजनी अग्रवाल ने बताया कि 16 अगस्त की शाम को आयोजित 'स्वरांजलि' में अनेक महिला कलाकार देशभक्ति से ओत-प्रोत प्रस्तुतियाँ देंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महिलाओं द्वारा प्रस्तुत ये प्रस्तुतियाँ संगीत प्रेमियों को भावविभोर करेंगी। डॉ. रजनी अग्रवाल ने सभी संगीत प्रेमियों से आग्रह किया है कि वे इस विशेष कार्यक्रम का भरपूर आनंद उठाएँ और बड़ी संख्या में शामिल होकर महिला कलाकारों को प्रोत्साहित करें।

जाट समाज ने उपाध्यक्ष तरड़ का स्वागत किया

श्रीगंगानगर। जाट समाज व जाट लोक सेवक समिति के संयुक्त तत्वावधान में भाजपा किसान मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष आत्माराम तरड़ का सुशील सिहाग के कार्यालय में जोरदार स्वागत व अभिनन्दन किया गया।

जाट लोक सेवक समिति के जगदीशराय कासनियां ने बताया कि स्वागत व अभिनन्दन समारोह में जाट समाज के गणमान्य व्यक्तियों व समिति के पदाधिकारियों ने तरड़ का माल्यार्पण कर स्वागत किया। उन्होंने बताया कि तरड़ पूर्व में भाजपा के श्रीगंगानगर जिलाध्यक्ष पद पर तथा किसान मोर्चा व संगठन के विभिन्न पदों पर रहकर आमजन की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव तत्पर रहे हैं विशेष रूप से किसानों की समस्याओं व श्रीगंगानगर जिले की ज्वलंत समस्याओं को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रीगणों को व्यक्तिगत रूप से मिलकर अवगत करवाते रहे हैं। तरड़ मिलनसार, ओजस्वी वक्ता, हंसमुख व्यक्तित्व के कारण आमजन में अपनी खास पहचान रखते हैं। सम्मान व स्वागत से अभिभूत आत्माराम तरड़ ने अपने सम्बोधन में कहा कि वे जाट समाज व जाट लोक सेवक समिति के आभारी हैं जिन्होंने इतना सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश के किसानों के साथ-साथ श्रीगंगानगर जिले के किसानों की समस्याओं के निराकरण का भरसक प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रदेश शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका निर्वह्न लगन व ईमानदारी से करेंगें। कार्यक्रम में धीराज डूडी,

हेतराम सहारण पूर्व सरपंच नेतेवाला, राजेन्द्र सहारण, इन्द्रपाल सहारण एडवोकेट, रामकुमार रोझ एडवोकेट, कृष्ण नैण, सुशील सिहाग, कृष्ण कूकणा, ओमप्रकाश सहारण, जगदीशराय कासनियां, ओमप्रकाश सहारण, रामप्रताप रणवां, जगदीश झोरड़, सुनील बैनीवाल, रामकुमार डूडी, दलीप गोदारा, कृष्ण रिणवा आदि उपस्थित रहे।

केंद्रीय कारागृह में नशामुक्ति अभियान का आयोजन

श्रीगंगानगर। सिख वर्ल्ड म्यूजिक एकेडमी, श्रीगंगानगर द्वारा नशामुक्ति जागरूकता एवं सामाजिक सरोकार के तहत केंद्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर में सांस्कृतिक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संगीत के माध्यम से सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने तथा नशे से दूर रहकर स्वस्थ एवं बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से सिख वर्ल्ड म्यूजिक एकेडमी के संस्थापक एवं निदेशक तथा प्रसिद्ध गायक सिमरजीत सिंह के नेतृत्व व निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक एवं संगीतमय प्रस्तुतियां दी गईं। कार्यक्रम के दौरान गीत-संगीत के माध्यम से नशे से दूरी, सकारात्मक जीवनशैली तथा समाज को नशामुक्त बनाने का प्रेरक संदेश दिया गया।

संस्थापक एवं निदेशक सिमरजीत सिंह ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के मन और विचारों को सकारात्मक दिशा देने का एक प्रभावी माध्यम भी है। संगीत के जरिए युवाओं एवं समाज के प्रत्येक वर्ग को नशे से दूर रहने तथा स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सिख

वर्ल्ड म्यूजिक एकेडमी भविष्य में भी सामाजिक जागरूकता, सांस्कृतिक गतिविधियों एवं नशामुक्ति अभियानों के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित करती रहेगी।

कार्यक्रम में सिख वर्ल्ड म्यूजिक एकेडमी के अध्यक्ष रजनेश बहल, उपाध्यक्ष हरजीत 'हैप्पी' मिगलानी, सचिव एवं कानूनी सलाहकार परमिंदर पाल सिंह, कानूनी सलाहकार नीरज गोयल, तरनवीर सिंह सहित पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। सफल आयोजन में कार्यक्रम समन्वयक सुनील मौर्य का विशेष सहयोग रहा।

केंद्रीय कारागृह प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों का भी कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग एवं प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। इस मौके पर जेल अधीक्षक महावीर प्रसाद मीणा, जेलर हेमराज वैष्णव सहित जेल प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

कार्यक्रम के माध्यम से संगीत के जरिए नशामुक्ति, सकारात्मक सोच एवं सामाजिक जागरूकता का एक महत्वपूर्ण और प्रभावी संदेश दिया गया।कार्यक्रम के अंत में सिख वर्ल्ड म्यूजिक एकेडमी के अध्यक्ष रजनेश बहल एवं संस्थापक व निदेशक सिमरजीत सिंह द्वारा जेल अधीक्षक महावीर प्रसाद मीणा एवं जेलर हेमराज वैष्णव को सम्मानित किया गया तथा जेल प्रशासन, अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया गया।

नगरीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 की तैयारियों की समीक्षा

हनुमानगढ़। आगामी नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 की तैयारियों एवं कानून-व्यवस्था को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. खुशाल यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों के चिन्हीकरण, सीमावर्ती क्षेत्रों में चेक पोस्ट स्थापित करने तथा गुंडा एक्ट एवं राजभाषा में दर्ज मुकदमों की स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

बैठक में सभी रिटर्निंग अधिकारियों को मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण, दावे-आपत्तियों के निस्तारण, मतदाता सूचियों के निरंतर अद्यतन, मतदाता सूचियों के भौतिक सत्यापन एवं सत्यापन के दौरान सामने आने वाली कमियों के निराकरण के निर्देश दिए गए। साथ ही मतदान केंद्रों की संख्या के आधार पर सेक्टरों का निर्धारण करने तथा रिटर्निंग अधिकारी स्तर पर नियंत्रण

कक्ष स्थापित करने के लिए भी निर्देशित किया गया।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता की पालना, पुलिस अधिकारियों के साथ कानून एवं व्यवस्था को लेकर समन्वय बैठक आयोजित करने तथा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इसके अलावा ईवीएम की तैयारी, मतगणना के लिए भवनों के चिन्हीकरण तथा निर्वाचन से संबंधित अन्य तैयारियों की भी समीक्षा की गई।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निर्वाचन संबंधी सभी कार्य समयबद्ध, समन्वित एवं त्रुटिरहित तरीके से पूरे किए जाएं तथा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए। बैठक में पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य, एडीएम उम्मेदीलाल मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविन्द, एसडीएम राहुल श्रीवास्तव, एसडीएम श्रीमती उमा मित्तल, जय कौशिक, भागीरथ राम, सत्यनारायण एवं विनोद कुमार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

नशीली गोलियों के साथ पकड़े आरोपी को 7 साल की जेल

रायसिंहनगर(सुखदीप सिंह)। नशीली गोलियां रखने के मामले में रायसिंहनगर एडीजे विपिन बिश्नोई की अदालत ने कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच अदालत के इस फैसले को अहम माना जा रहा है।

अपर लोक अभियोजक मोहनलाल बाना ने बताया कि मामला जैतसर पुलिस थाना क्षेत्र का है। 10 फरवरी 2020 को जैतसर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नरेश कुमार उर्फ राकेश लूथरा निवासी वार्ड नंबर 6, जैतसर को नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नशीली गोलियां बरामद करने के बाद उसके खिलाफ नियमानुसार मामला दर्ज किया था। पुलिस ने प्रकरण की जांच पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। इसके बाद मामले की न्यायालय में सुनवाई चली। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले से जुड़े साक्ष्य और दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों को सुनने और मामले में उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी माना।

सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे विपिन बिश्नोई की अदालत ने आरोपी नरेश कुमार उर्फ राकेश लूथरा को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। आरोपी गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक अभिरक्षा में था।अदालत के इस फैसले से नशीली गोलियों की अवैध बिक्री और तस्करी में लिप्त लोगों को कड़ा संदेश गया है। पुलिस की ओर से दर्ज किए गए मामले में लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद दोष सिद्ध होने पर आरोपी को अब कठोर कारावास भुगतना होगा।

कांग्रेस नेता पंच का किया बहुमान

द सांध्यदीप नेटवर्क,ब्यावर(दिलीप सिंह)। कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ की ओर से ब्यावर विधानसभा क्षेत्र (103) के दो बार कांग्रेस प्रत्याशी रहे, राज.प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य पारसमल जैन पंच का राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग सं.58 ब्यावर-उदयपुर पर रिंग पुलिया के निकट स्थित उनके कार्यालय में प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉ.नरेंद्र काठात के नेतृत्व में फूलमाला पहना व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया।

इस मौके जिला उपाध्यक्ष सद्दाम हुसैन, संगठन महासचिव डॉ.जितेंद्र खींचा एवं ब्यावर ब्लॉक अध्यक्ष फैसल खान सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। उपस्थित पदाधिकारियों ने राज.निकाय व पंचायत राज आम चुनाव-2026 में आपसी एकजुटता,सेवा भावना और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया।

खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति की बैठक आयोजित

हनुमानगढ़। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार जिले में खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में गिव-अप अभियान, खाद्य सुरक्षा योजना में नवीन पात्र लाभार्थियों को जोड़ने, आधार सीडिंग, ई-केवाईसी एवं एलपीजी मैपिंग सहित खाद्य सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा की गई।

बैठक में गिव-अप अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए अपात्र व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई एवं अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर दिया गया। साथ ही खाद्य सुरक्षा योजना में नवीन पात्र लाभार्थियों को जोड़ने की प्रक्रिया को सुचारू एवं पारदर्शी बनाने तथा पात्र परिवारों को समय पर योजना का लाभ उपलब्ध करवाने को लेकर चर्चा की गई।

बैठक में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की आधार सीडिंग, ई-केवाईसी एवं एलपीजी मैपिंग की स्थिति की भी समीक्षा की गई। समिति सदस्यों से इन कार्यों के क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया गया, ताकि पात्र लाभार्थियों से संबंधित लंबित प्रक्रियाओं को समयबद्ध रूप से पूरा किया जा सके।

बैठक में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं जवाबदेह बनाने तथा योजना का लाभ वास्तविक पात्र परिवारों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। संबंधित अधिकारियों एवं कार्मिकों को समिति सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए लंबित कार्यों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में जिला रसद अधिकारी सुनील कुमार घोड़ेला, प्रवर्तन अधिकारी बाबूलाल जानू एवं योगेश मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक मनीष सिंगला एवं पुरुषोत्तम सहित समिति के सदस्यों ने भाग लिया। हनुमानगढ़, संगरिया, भादरा, नोहर एवं रावतसर तहसील क्षेत्रों से समिति सदस्य भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री का अनूपगढ़ दौरा : डीएम-एसपी ने किया सभास्थल का अवलोकन

श्रीगंगानगर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 14 अगस्त को जिले के अनूपगढ़ क्षेत्र में प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर मंगलवार को जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव ने सभा स्थल का अवलोकन किया। इस दौरान जिला कलक्टर द्वारा मुख्यमंत्री के प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम के संबंध में की जा रही तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि संबंधित विभागीय अधिकारी निर्धारित कार्यों को निष्ठापूर्वक पूर्ण करें। जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने भी कानून व्यवस्था के तहत तैयारियों का जायजा लिया।

इस अवसर पर एडीएम प्रशासन सुभाष कुमार, एडीएम अनूपगढ़ अशोक सांगवा, एसडीएम अनूपगढ़ दीपक चंदन, एसडीएम रायसिंहनगर पूनमचंद सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।